वर्ष-14 - अंक 89
पृष्ट-04 मूल्य : 01 रुपया

सीतापुर
बुधवार,08 जुलाई 2026

RNI.No. UHIN/2012/43078

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.......
9511151254

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

swatantraprabhat.com

epaper.swatantraprabhat.com

जो लिखेगा, वही टिकेगा

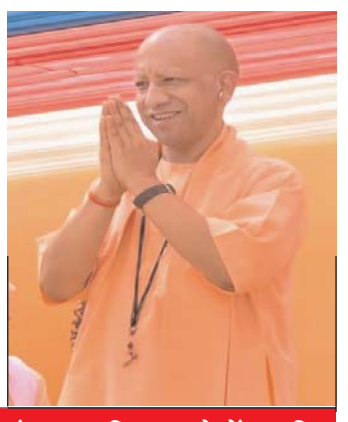

लखनऊ से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून गाज़ियाबाद , दिल्ली ,पंजाब , हरियाणा ,चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

बिसवां के किसान को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में प्रथम स्थान, जिले के लिए गौरव का क्षण 3
श्रीलंका की जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प: 25 की मौत, 100 घायल 4
नव भारत साक्षरता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के 11.69 लाख लोग हुए साक्षर 02

ताजमहल या तेजो महालय? ASI कैसे पता लगाता है प्राचीन इमारतों की असलियत

ताज महल एक बार फिर अदालत में चर्चा का विषय बन गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार यानी 06 जून को ताजमहल में 'तेजो महालय' शिव मंदिर होने के दावे और सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट में यह याचिका 3 जुलाई को अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर, सीनियर एडवोकेट हरि शंकर जैन समेत 5 लोगों की ओर से दाखिल की गई थी. ताजमहल को लेकर 2015 में एक केस दर्ज किया गया इस केस में ये घोषित करने की मांग की गई है कि ताजमहल के परिसर में अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय का मंदिर मौजूद है. केस के जल्द से जल्द निपटारे के लिए सर्वे कराने और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी लगाई गई थी. लेकिन जिला अदालत ने इसे नामंजूर कर दिया था.जिला अदालत के इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट की तरफ से जारी निर्देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है. इस संस्था का काम देश की जमीन में गड़े हजारों साल पुराने इतिहास की खोजबीनकरना, उसकी असलियत की जानकारी देना और ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल करना है. आइए जानते हैं कि कैसे स्थ्र हजारों साल पुराने ढांचे के मंदिर-मस्जिद के होने की असलियत को बताता है. हजारों साल पहले के किसी ढांचे की असलियत पता लगाने के लिए

कई वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाता है. सबसे पहले वह पता करता है ढांचे के नीचे कुछ खुदाई लायक है भी या नहीं. अगर तकनीकों के आधार पर उसे ढांचे या जमीन के अवशेषों की डेंसिटी, उसके आकार और मटेरियल को लेकर पुख्ता जानकारी मिलती है, तभी वह आगे की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ता है. साइज़्मिक मेथड- इसमें साइज्मिक वेब का इस्तेमाल किया जाता है. यह वह तरंगे होती हैं, जो भूकंप के समय निकलती है. आर्कियोलॉजिस्ट इसे मशीनों के जरिए ढांचे के नीचे साइज़्मिक तरंगे रिलीज करते हैं. मिट्टी से गुजरते हुए जब किसी दीवार के अवशेष से टकराकर, इनमें से कुछ तरंगे वापस आती हैं, तो कुछ डिफलेक्ट हो जाती हैं. इससे दो जानकारियां हासिल होंगी. डिफलेक्ट हुई तरंगों से जमीन के नीचे दीवार की अवशेष ईंट की है या फिर पत्थर की. वहीं, रिफ्लेक्ट तरंगे बताएंगी कि दीवार के अवशेष ज़मीन से कितने नीचे हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड- अगर कहीं जमीन के नीचे सड़क या दीवार के अवशेष होते हैं वहां पत्थरों और ईंटों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आ जाता है.इसे मैग्नेटोमीटर के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है. आर्कियोलॉजिस्ट इसी का इस्तेमाल कर जमीन के नीचे सड़क, दीवार समेत अन्य ढांचों के बारे में पता लगाते हैं. ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार-इस तकीनीक के जरिए ऑर्कियोलॉजिस्ट एक मशीन के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकालते हैं, जो जमीन के अंदर जाती है. यह तरंगे जब रिफलेक्ट होती है तो कंप्यूटर पर ज़मीन के अंदर दबे ढांचे की 3 ष्ठ तस्वीर बना देते हैं. जमीन के अंदर किसी भी तरह के दबे ढांचे की असलियत पता लगाने के लिए इसे सबसे सटीक तकनीक माना जाता है. इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल सूखी रेत वाली मिट्टी के नीचे दबे ढांचों के बारे में पता लगाने के लिए होती है.

जमीन के नीचे ढांचे की कंफर्मेशन के बाद क्या करता है ASI?

ऊपर दिए गए तकनीकों के इस्तेमाल से दजू जमीन के नीचे बने ढांचों के बारे में पूरी तरह कंफर्मेशन मिल जाती है तभी भारतीय पुरातत्व विभाग ढांचे की असलियत के बारे में पता लगाने के लिए खुदाई करता है. इसके लिए चिह्नित ज़मीन को छोटी-छोटी वर्गाकार में बांटा जाता है. फिर धीरे-धीरे सतर्कता से खुदाई की जाती है. फिर जाकर विभाग को जमीन के नीचे अवशेष, दीवार, सड़क या फिर पूरा का पूरा शहर मिलते हैं.साइज़्मिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार किसी भी तकनीक के इस्तेमाल में जमीन के ऊपर या फिर नीचे बने ढांचे को नुकसान नही पहुंचता है.

कार्बन डेटिंग का क्यों और कैसे इस्तेमाल किया जाता है?

खुदाई के दौरार ढांचे से मिली प्राचीन वस्तु की आयु का अनुमान लगाने के लिए कार्बन डेटिंग की तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, इससे केवल उन्हीं सामग्रियों की असलियत और उम्र पता चलती है, जिनमें कभी जीवन (कार्बन) मौजूद था. प्राचीन काल की इमारतों में चूने का मसाला बनाने के लिए जैविक चीजों का इस्तेमाल होता था, जब यह मसाला सूखता है, तो यह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है. इसके अलावा ढांचे की खुदाई से मिले लकड़ी, हड्डियां, या कोयला पत्थर या धातु की जांच से भी उसकी उम्र पता लगाने की कोशिश की जा सकती है.

शिलाओं और सिक्कों से भी ASI ढांचे की उम्र का करता है पता

खुदाई के समय शिलाओं या दीवारों पर लिखी हुई लिपियों की मदद से उसके समयकाल के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है. इससे यह पता लग सकता है कि यह लिपि कितनी पुरानी है और किस शासनकाल की है. जमीन के नीचे दबा ढांचा भी उसी समयाकाल का हो सकता है. इसके अलावा खुदाई में मिले सिक्के भी उसके समयकाल के बारे में संभावित जानकारी देते हैं.

पहले 10 मिनट की डेडलाइन, अब एक्शन... अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे को भेजा मानहानि का नोटिस

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चुराने के आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और क्ष्छ्रक्र सांसद निशिकांत दुबे के बीच ठन गई है. निशिकांत के आरोपों के बाद मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने उन्हें मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है. इससे पहले अखिलेश ने निशिकांत को 10 मिनट में टिन्नू से जोड़े गए पोस्ट को हटाने की डेडलाइन दी थी. इसके बाद भी पोस्ट नहीं हटाने पर उनकी पार्टी ने मंगलवार निशिकांत दुबे को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है. अखिलेश ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष केके पाल के जरिए निशिकांत दुबे को ये नोटिस भिजवाया है. बताया जा रहा है कि ये नोटिस अखिलेश और टिन्नू के बीच कथित बातचीत के आरोपों से जुड़ा है. अखिलेश ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया है.

लीगल नोटिस में क्या है लिखा?

समाजवादी पार्टी ने अब औपचारिक रूप से मानहानि का लीगल नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. नोटिस में मांग की गई है कि निशिकांत दुबे पोस्ट हटाएं और सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अखिलेश यादव ने दूसरों को भी चेतावनी दी है कि वे ऐसी पोस्ट हटा दें और माफी मांगें.

जानें क्या है पूरा विवाद

निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र से BJP सांसद हैं. उन्होंने 5 जुलाई को सर्वन्ना प्रसाद बालासुब्रमण्यम का एक X पोस्ट शेयर किया, जिसमें दावा किया गया था कि आरोपी टिन्नू यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नियमित संपर्क में था. सर्वन्ना ने पुलिस जांच और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड का हवाला देते हुए यह दावा किया था. निशिकांत ने लिखाः 'तो, टिन्नू टीपू से बात कर रहा था, है ना? '

निशिकांत के पोस्ट पर भड़के अखिलेश

अखिलेश यादव निशिकांत दुबे के पोस्ट से बहुत नाराज थे. उन्होंने दुबे को 10 मिनट की समय-सीमा देते हुए पोस्ट हटाने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि 'BJP सांसद को 10 मिनट के भीतर अपना झूठा सोशल मीडिया पोस्ट हटाना होगा. वरना, उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज की जाएगी.' संसदीय मर्यादा, शिष्टाचार और भगवान राम से जुड़ी गरिमा का हवाला देते हुए अखिलेश ने इसे झूठा प्रचार बताया. उन्होंने कहा कि यह BJP द्वारा स्क्र के 'PDA' गठबंधन को बदनाम करने की कोशिश थी.

दुबे समेत कई लोगों के खिलाफ पुलिस से की शिकायत

इस बीच, स्क्र नेताओं ने इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में निशिकांत दुबे और सोशल मीडिया पर मौजूद कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने दावा किया था कि टिन्नू और अखिलेश के बीच ऐसी बातचीत हुई थी. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

अखिलेश की चेतावनी पर दुबे का पलटवार

निशिकांत दुबे ने भी अखिलेश की चेतावनी पर टिप्पणी की. उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखाः 'जल्दी करो; आप इतने परेशान क्यों हैं? मैंने बस एक सवाल ही तो पूछा था, है ना? 1990 में राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? मैं कोर्ट जाऊंगा. '

मानहानि नोटिस पर निशिकांत दुबे का अखिलेश पर हमला

सपा के मानहानि के नोटिस पर निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक्स पर किए पोस्ट में लिखा, अगर मानहानि हुई है, तो कानूनी नोटिस सीधे उनकी तरफ से आना चाहिए, क्योंकि कानून में यही प्रावधान है. दुबे ने दावा किया कि चूंकि वह उस समिति के सदस्य थे जिसने यह कानून तैयार किया था, इसलिए वह इसके प्रावधानों से अच्छी तरह वाकिफ हैं. पोस्ट में दुबे ने अखिलेश यादव के वकीलों पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे वकील उनकी बदनामी करा रहे हैं. उन्होंने अखिलेश यादव की सेहत पर भी तंज कसते हुए लिखा, 'आपने अपनी क्या हालत बना ली है? आप कुछ लेते क्यों नहीं? कम से कम विक्स की गोली ही खा लीजिए. '

संक्षिप्त ख़बरें

नशे में टल्ली दूल्हा, दहेज में बुलेट की मांग मुजफ्फरनगर में शराबी दूल्हे का हंगामा, दुल्हन ने लौटा दी बारात

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार को एक शादी समारोह उस समय विवाद में बदल गया, जब दूल्हा शराब के नशे में दुल्हन के घर पहुंचा. दूल्हे की हालत देखकर दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया. घटना के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें दूल्हा नेकर-बनियान में चारपाई पर लेटा दिखाई दे रहा है. जानकारी के अनुसार, फुगाना थाना क्षेत्र के डूंगरपुर गांव निवासी शिवम की बारात बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के टांडा माजरा गांव में करिश्मा से शादी के लिए पहुंची थी. आरोप है कि बारात के दौरान दूल्हे के दोस्तों ने उसे इतनी शराब पिला दी कि वह दुल्हन के दरवाजे पर अपने पैरों पर भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था.

दहेज में मांग रहा था बुलेट

दुल्हन पक्ष का आरोप है कि विरोध करने पर दूल्हे ने नशे की हालत में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग भी कर दी. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और हंगामा शुरू हो गया. स्थिति बिगड़ने पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया. दुल्हन करिश्मा ने कहा कि उन्होंने ऐसे दूल्हे को वापस लौटा दिया और समाज को संदेश दिया कि ऐसे युवक से किसी को अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए.

शादी में खर्च हुए सात लाख

दुल्हन के पिता सरदामल ने बताया कि दूल्हा पूरी तरह नशे में था और उसे होश तक नहीं था. उनका कहना है कि शादी की तैयारियों में लगभग सात लाख रुपये खर्च हुए, जिनमें से अधिकांश रकम कर्ज लेकर जुटाई गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान मारपीट भी हुई और अब वे शादी में हुए खर्च की भरपाई चाहते हैं.

पुलिस ने क्या कहा?

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। क्षेत्राधिकारी (सीओ) बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि टांडा माजरा गांव में बारात आने के बाद दुल्हन पक्ष ने दूल्हे के नशे में होने का आरोप लगाया, जिसके चलते दोनों पक्षों में कहासुनी हुई. पुलिस के अनुसार, बारात को बंधक बनाए जाने की बात सही नहीं है. उन्होंने कहा कि जो भी लिखित शिकायत मिलेगी, उसके आधार पर कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ: 15 बांग्लादेशी और रोहिंग्या दोषियों को 5-5 साल सजा, NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले 15 लोगों को लखनऊ की विशेष अदालत ने 5-5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही इन लोगों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. इनमें 13 बांग्लादेशी नागरिक और दो रोहिंग्या शामिल हैं. ATS ने 26 अक्टूबर 2021 को इस गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था. जिन लोगों को NIA कोर्ट ने सजा सुनाई है उनमें महफूजुर रहमान ,अल अमीन अहमद, खोखन सरदार, अलाउद्दीन तारीक,जमील अहमद, हुसैन मोहम्मद फहद, शखावत खान, असीदुल इस्लाम, जैनुल इस्लाम ,राजीव हुसैन, मोमिनुर इस्लाम, मेहंदी हसन, शाओन अहमद ,मोहम्मद जमील और नूर अमीन शामिल हैं. उत्तर प्रदेश ATS द्वारा सीमा पार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किए जाने के लगभग पांच साल बाद NIA कोर्ट के न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने यह फैसला सुनाया,

पश्चिम बंगाल में छिप कर रह रहे थे

ये सभी बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में छिप कर रह रहे थे. साजिश के तहत मिथुन

मंडल, विक्रम सिंह, महफूज और समीर मंडल उर्फ टोनी, मोहम्मद जमील और कुछ अन्य लोग बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में घुसपैठ करा रहे हैं.

फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाए

जांच में सामने आया कि ये लोग सिंडिकेट बनाकर बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराते हैं. इन लोगों का फर्जी भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट तक बनवा रहे हैं. ATS ने कोर्ट को बताया कि कई बांग्लादेशी ,रोहिंग्या का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट तक बनवाया गया है, जिन्हें मानव तस्करी के जरिए कई देशों में भेजा भी गया है. अक्टूबर 2021 में इन सभी को अलग-अलग जगह से ATS ने किया था गिरफ्तार. ATS ने जांच पूरी कर सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.

ATS को मिली थी जानकारी

दरअसल ATS को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि एक आपराधिक साजिश के तहत मिथुन मंडल, विक्रम सिंह, महफुजूर, समीर मंडल उर्फ टोनी, मो. जमील और अन्य कुछ बांग्लादेश के लोगों के साथ भारत में घुसपैठ करा रहे हैं. ये लोग एक सिंडिकेट बनाकर बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों को अवैध रूप से भारत-बांग्लादेश सीमा में प्रवेश कराकर उनकी पहचान बदलकर भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित करने के लिए उनका फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड व पासपोर्ट भी बनवा रहे थे.

PM मोदी ने इंडोनेशिया में भारतीयों को किया संबोधित, दोनों देशों के ष्ठहृ को बताया एक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

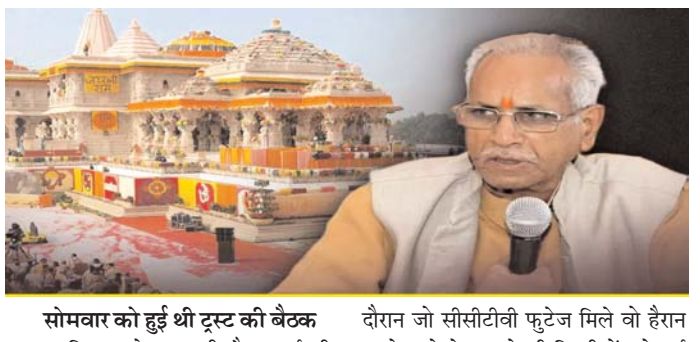

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीयों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्राबोवो ने गर्व से कहा कि उनमें भारतीय DNA है. उस एक वाक्य से उन्होंने लाखों भारतीयों का दिल जीत लिया. पीएम ने कहा, 'मैं यह कहना चाहता हूं कि DNA आपसी भरोसे, साझा इतिहास और साझा सभ्यतागत विरासत पर आधारित होता है. भारत और इंडोनेशिया के बीच का रिश्ता सभ्यताओं का रिश्ता है. साम्राज्य बने और मिटे और वैश्विक राजनीति बदली, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच का यह अटूट बंधन हमेशा बना रहा है. यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है'.उन्होंने आगे कहा, 'मैं यहां जहां भी गया, जिससे भी मिला, हर चेहरे पर भारत के लिए प्यार, सम्मान और अपनापन साफ दिखाई दिया. मैंने देखा कि भारतीय गाना 'कुछ कुछ होता है...' यहां बहुत पॉपुलर है. आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो को इस बारे में बताया और कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ चलते हैं, तो यह 'कुछ कुछ' से आगे बढ़कर 'बहुत कुछ' बन जाता है. आज मुझे सुबह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलने का भी सौभाग्य मिला. इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सम्मान...यह 140 करोड़ भारतीयों की शान है. यह अवॉर्ड इंडोनेशिया और भारत के बीच गहरी दोस्ती का एक और प्रतीक है'.

PM ने की फीफा वर्ल्ड कप की बात

पीएम ने कहा, 'आज कल दुनिया में फुटबॉल फीवर चल रहा है. यहां इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है. आप सभी वो एनर्जी, वो जोश...यहां भी लेकर आए हैं और दिखाई दे रहा है. और एक अजब संयोग बना है कि जब भी मैं इंडोनेशिया आया हूं, फीफा वर्ल्ड कप का तूफान छाया होता है, लेकिन इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग मैन ऑफ द मैच हैं. आज का ये आयोजन भव्य भारत की जीती-जागती तस्वीर बने हैं'.

'भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव'

पीएम मोदी ने दोनों देशों के सांस्कृतिक जुड़ाव को लेकर भी कहा कि चाहे महानदी में केले के छिलके से बनी छोटी नावें बहाने की परंपरा हो, 'वायांग कुलित' के जरिए महाभारत का मंचन हो या फिर 'देवी श्री' की पूजा, हर परंपरा भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाती है. इस रिश्ते का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही समृद्ध भी है.

पीएम मोदी ने इंडोनेशिया को बताया अच्छा दोस्त

उन्होंने कहा कि 'भारत अपने समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बंदरगाहों को आधुनिक बना रहा है, नए जहाज बना रहा है और समुद्री रास्तों की खोज कर रहा है, ऐसे में इंडोनेशिया हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है. इंडोनेशिया हो या भारत, हमारा साझा लक्ष्य विकास है. हम न तो इंतजार कर सकते हैं और न ही रुक सकते हैं. आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है. जब कोरोना का इतना बड़ा संकट दुनिया पर आया, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था रुकी नहीं. जब पश्चिम एशिया में इतना बड़ा संकट चल रहा था, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था थमी नहीं'. पीएम मोदी ने कहा, 'पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की विकास दर 7.7% रही. यह रफ्तार भारत में किए गए सुधारों का नतीजा है. हमने अच्छा प्रदर्शन किया और इसीलिए भारत में बदलाव आ रहा है. यह रफ्तार, यह तरक्की, यूं ही नहीं आई है. भारत ने एक के बाद एक कई सुधार किए हैं, हमने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. इसीलिए आज देश बदल रहा है. सुधार (Reforms), प्रदर्शन (Perform), बदलाव (Transform), हम इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं. भारत की तरक्की की रफ्तार और दायरा, अगर मुझे इसे एक लाइन में बताना हो, तो मैं कहूंगा कि 1.4 अरब लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं आगे बढ़ रही हैं'.

'परम गोपनीय SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, मैंने मौन धारण कर लिया...', चंपत राय बोले- समय पर जवाब दूंगा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का पहला बयान सामने आया है. चंपत राय ने राम भक्तों के नाम लिखी एक चिट्ठी में कहा है कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि SIT की फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उसके आने के बाद मैं हर सवाल का जवाब दूंगा. चंपत राय ने पत्र में लिखा है कि SIT की रिपोर्ट आने तक मैंने मौन धारण कर लिया है. चढ़ावा चोरी को लेकर मुझपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं. मुझे लेकर अनेकों प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं.मैं वर्ष अक्टूबर 1991 से अयोध्या में भेजा गया संगठन द्वारा, मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से, जहां-जहां मैं रहा, खुली पुस्तक के समान है.

'गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है'

चंपत राय ने एसआईटी की रिपोर्ट को परम गोपनीय बताते हुए कहा कि अब यह सार्वजनिक हो चुकी है. यद्यपि यह 'परम गोपनीय' थी, आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि SIT के अन्तिम रिपोर्ट आने के बाद, फैलाये जा रहे, सभी बिन्दुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा, सभी सत्य सामने आ जाएगा.

सोमवार को हुई थी ट्रस्ट की बैठक

एक दिन पहले ट्रस्ट की बैठक हुई थी जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था. ट्रस्ट की मीटिंग में शामिल लोगों ने कहा कि चढ़ावा चोरी के आरोपों से बदनामी झेलनी पड़ रही है. इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए. ट्रस्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करते हुए अगली बैठर 22 जुलाई को बुलाई है.

एसआईटी ने रिपोर्ट में गिनाई कमियां

एसआईटी की जो अंतरिम रिपोर्ट सामने आई है उसमें चढ़ावा से लेकर प्रबंधन तक कई खामियां गिनाई गई हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर प्रबंधन की ओर से SOP का भी ठीक तरह से पालन नहीं किया गया. साथ ही साथ-साथ यह भी बताया गया कि जांच के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज मिले वो हैरान करने वाले थे. चढ़ावे की गिनती में लगे कई कर्मचारी अपने जेब और मोजे में पैसे रखकर जाते दिखे हैं.

चाबियों पर टिन्नू यादव का कंट्रोल

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव बिना किसी लिखित या औपचारिक प्राधिकार के हंडियों की चाबियों और उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं को नियंत्रित कर रहा था. SIT ने उनकी भूमिका को अपराध की साजिश, अभिप्रेरण और अपराध को सुगम बनाने के दृष्टिकोण से गंभीर मानते हुए उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कर जांच किए जाने की सिफारिश की थी. टीनू यादव की गिनती चंपत राय के बेहद करीबियों में होती है.कार्ड, पैन कार्ड व पासपोर्ट भी बनवा रहे थे.

रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, DCPCR में अध्यक्ष और 4 नए सदस्यों की नियुक्ति

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सरकार ने लगभग 3 वर्षों से रिक्त दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) का पुनर्गठन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के माध्यम से DCPCR का पुनर्गठन करते हुए आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनका कल्याण दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. यह नियुक्तियां बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2008 और भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी संबंधित अधिसूचना के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए की गई हैं. अधिसूचना के मुताबिक, ओम प्रकाश व्यास को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही राहुल गौतम, कुंदन

कंसकार, स्वाति गुप्ता और मोनिका शर्मा को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है.

3 वर्ष का होगा कार्यकाल

सभी नियुक्तियां उस तारीख से प्रभावी होंगी जब संबंधित व्यक्ति अपने पदों का कार्यभार संभालेंगे.प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा. हालांकि अगर इससे पहले निर्धारित आयु सीमा पूरी हो जाती है तो कार्यकाल उसी दिन समाप्त हो जाएगा. आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 60 वर्ष निर्धारित की गई है. क्या बोलीं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर बच्चा सुरक्षित, सम्मानजनक और अवसरों से भरपूर बचपन का हकदार है. दिल्ली सरकार बच्चों के अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मजबूत और सक्रिय होना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

प्रत्येक बच्चे के हितों की होगी रक्षा

उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि आयोग का नया नेतृत्व पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए बच्चों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. हमारी सरकार प्रत्येक बच्चे के हितों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रहेगी.

संपादकीय

अयोध्या : श्रद्धा व्यवस्था और जिम्मेदारी

अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला जांच में दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है चैट में खुलासा हुआ है कि दो करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ है। ऐसे में एक सवाल यह उठता है कि आखिर कि लोगों की श्रद्धा से खिलवाड़ कब तक चलेगा। अयोध्या केवल एक शहर नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का केंद्र है। सदियों से यह भगवान श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में गिनी जाती रही है। श्रीराम मंदिर के निर्माण और प्राण-प्रतिष्ठा के बाद देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ऐसे में यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सम्मानजनक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण मिले। लेकिन जब अव्यवस्था, लापरवाही, भ्रष्टाचार, श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार या आस्था के नाम पर ठगी जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली स्थिति बन जाती है। इसी संदर्भ में 'अयोध्या में आस्था से खिलवाड़' का विषय गंभीर चर्चा की मांग करता है। श्रीराम मंदिर बनने के बाद अयोध्या विश्वस्तरीय धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन चुका है। प्रतिदिन हजारों और विशेष अवसरों पर लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के लिए सुचारु यातायात, स्वच्छता, सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, आवास और दर्शन की बेहतर व्यवस्था आवश्यक है। यदि इन व्यवस्थाओं में कमी रह जाती है तो श्रद्धालुओं का अनुभव प्रभावित होता है और धार्मिक स्थल की गरिमा पर भी प्रश्नचिह्न लगते हैं। आस्था से खिलवाड़ केवल धार्मिक भावनाओं का अपमान करने तक सीमित नहीं है। इसके कई रूप हो सकते हैं— श्रद्धालुओं से अवैध वसूली या अधिक शुल्क लेना। दर्शन के नाम पर वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा देना। नकली प्रसाद, दान और पूजा के नाम पर धोखाधड़ी। सफाई और मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी। भीड़ प्रबंधन में लापरवाही। श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार या शोषण।धार्मिक स्थल के आसपास अवैध कब्जे और अव्यवस्थित व्यापार। इन सभी परिस्थितियों में नुकसान केवल श्रद्धालुओं का ही नहीं होता, बल्कि अयोध्या की प्रतिष्ठा और धार्मिक पर्यटन की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। सरकार और प्रशासन ने अयोध्या के विकास के लिए बड़े पैमाने पर सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया है। यह सराहनीय प्रयास है। लेकिन केवल भौतिक विकास पर्याप्त नहीं है। व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी, शिकायतों का त्वरित समाधान, पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है। यदि किसी श्रद्धालु को दर्शन में कठिनाई होती है, कोई सुविधा नहीं मिलती या उसके साथ धोखाधड़ी होती है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर सेवा का भाव सर्वोपरि होना चाहिए।अयोध्या के स्थानीय नागरिक, व्यापारी, होटल संचालक, पुजारी और सेवा प्रदाता भी इस धार्मिक नगरी की पहचान हैं। यदि वे ईमानदारी और सेवा भावना के साथ कार्य करेंगे तो श्रद्धालु सुखद अनुभव लेकर लौटेंगे। लेकिन यदि कुछ लोग लालच में आकर श्रद्धालुओं का आर्थिक या मानसिक शोषण करते हैं, तो उसका नकारात्मक प्रभाव पूरे शहर की छवि पर पड़ता है। आज सोशल मीडिया पर किसी भी घटना का वीडियो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। कई बार वास्तविक घटनाएं सामने आती हैं, तो कई बार अधूरी जानकारी या भ्रामक वीडियो भी वायरल हो जाते हैं। इसलिए प्रशासन को तथ्यात्मक जानकारी समय पर उपलब्ध करानी चाहिए और लोगों को भी बिना पुष्टि के किसी जानकारी को साझा करने से बचना चाहिए। अयोध्या का नाम अक्सर राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र भी बन जाता है। लोकतंत्र में आलोचना और चर्चा स्वाभाविक है, लेकिन धार्मिक आस्था को राजनीतिक लाभ या नुकसान के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं माना जा सकता। मंदिर और श्रद्धालुओं से जुड़े मुद्दों पर सभी पक्षों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। अयोध्या की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं— श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाए।अवैध वसूली और धोखाधड़ी के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। शिकायत निवारण प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाया जाए। स्थानीय व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।स्वच्छता, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की निरंतर निगरानी हो। श्रद्धालुओं की सही जानकारी देने के लिए अधिकृत सहायता केंद्र स्थापित किए जाएं।अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव की अपेक्षा लेकर आता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़—चाहे वह अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, शोषण या लापरवाही के रूप में हो—बिल्कुल भी स्वीकार न किया जाए। विकास के साथ-साथ संवेदनशील प्रशासन, ईमानदार व्यवस्था और सेवा की भावना ही अयोध्या की वास्तविक पहचान को मजबूत करेंगी। आस्था का सम्मान तभी सार्थक होगा जब श्रद्धालुओं का विश्वास हर स्तर पर सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।

राजीव शुक्ला -(संपादक)

मेष –मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि आपके करीबी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करने से बचें।

वृषभ–वृषभ राशि के जातकों के लिए व्यापार में छोटे–छोटे सौदे भी अच्छा लाभ दिला सकते हैं। शिक्षा से जुड़े लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

मिथुन –मिथुन राशि के जातकों पर आज कार्यों को समय पर पूरा करने का दबाव रह सकता है। छोटी–छोटी बातों को लेकर तनाव महसूस हो सकता है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें। यदि यात्रा टाली जा सकती है तो फिलहाल ऐसा करना बेहतर रहेगा।

कर्क –कर्क राशि के जातकों के लिए आज भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है। भाई–बहनों के साथ बातचीत के दौरान संयम बनाए रखें। विदेश से जुड़े व्यापार या शिक्षा के मामलों में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं।

सिंह–सिंह राशि के जातकों को आज अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखने की आवश्यकता है। शोध और नए विषयों पर काम करने वालों को सफलता मिल सकती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार और करीबी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा।

कन्या –कन्या राशि के जातकों के लिए आज व्यापार और करियर से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रगति होगी। जीवनसाथी की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। समाज में मान–सम्मान बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं।

तुला –तुला राशि के जातकों को आज विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। कार्यों की गति अपेक्षा से धीमी रह सकती है। सुख–सुविधाओं पर अधिक खर्च होने से आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्कता बनाए रखें।

वृश्चिक –वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रह सकता है। अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें। दूसरों की सहायता करने से मानसिक संतोष मिलेगा और कार्यों में भी गति बनी रहेगी।

धनु –धनु राशि के जातकों को आज पहले किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। परिवार में यदि लंबे समय से कोई तनाव चल रहा है तो उसे दूर करने में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना बेहतर रहेगा।

मकर–मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है। संतान से जुड़े मामलों में धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है।

कुंभ –कुंभ राशि के जातकों का आज कामकाज में मन कम लग सकता है। दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन हल्का रहेगा। विरोधियों पर आप अपनी समझदारी से बढ़त बनाए रखने में सफल रह सकते हैं।

मीन –मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने की संभावना है। कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

नव भारत साक्षरता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के 11.69 लाख लोग हुए साक्षर

जो व्यक्ति पढ़ना-लिखना नहीं जानता, वह सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों को समझने, बच्चों की शिक्षा में सहयोग देने और आधुनिक तकनीकी संसाधनों का लाभ उठाने में कठिनाई महसूस करता है। ऐसे में साक्षरता केवल शिक्षा नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन और आत्मनिर्भरता की कुंजी बन जाती है। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर नागरिकों को साक्षर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर ''नव भारत साक्षरता कार्यक्रम'' संचालित किया जा रहा है। इस अभियान ने बीते वर्षों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक आयोजित साक्षरता मूल्यांकन परीक्षाओं में कुल 13,81,530 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 11,68,292 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक साक्षरता प्राप्त की। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हो। यही कारण है कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, निपुण भारत मिशन को लागू करने और उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार के साथ-साथ वयस्क साक्षरता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा को केवल विद्यालयों और महाविद्यालयों तक सीमित न रखकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, आत्मनिर्भरता और जनसशक्तीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हुए अनेक अभिनव कार्य शुरू किये हैं। इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में संचालित नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आज लाखों लोगों के जीवन में आशा, आत्मविश्वास और नए अवसरों का संचार कर रहा है। निरक्षरता केवल अक्षरों को न पहचान पाने की स्थिति नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास की राह में एक बड़ी बाधा भी होती है। जो व्यक्ति पढ़ना–लिखना नहीं जानता, वह सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने, बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों को समझने, बच्चों की शिक्षा में सहयोग देने और आधुनिक तकनीकी संसाधनों का लाभ उठाने में कठिनाई महसूस करता है। ऐसे में साक्षरता केवल शिक्षा नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन और आत्मनिर्भरता की कुंजी बन जाती है। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर नागरिकों को साक्षर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर ''नव भारत साक्षरता कार्यक्रम'' संचालित किया जा रहा है। इस अभियान ने बीते वर्षों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक आयोजित साक्षरता मूल्यांकन परीक्षाओं में कुल 13,81,530 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 11,68,292 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक साक्षरता प्राप्त की। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हो। यही कारण है कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, निपुण भारत मिशन को लागू करने और उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार के साथ–साथ वयस्क साक्षरता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इसी व्यापक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सामुदायिक भागीदारी है। कार्यक्रम के अंतर्गत पहले असाक्षर व्यक्तियों की पहचान की जाती है। इसके बाद प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा वालंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। यही वालंटियर्स गांवों, कस्बों और शहरी क्षेत्रों में साक्षरता कक्षाओं का संचालन करते हैं। शिक्षण कार्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संचालित किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल लोगों को पढ़ना–लिखना सिखाना नहीं है। इसके माध्यम से प्रतिभागियों को गणना, दैनिक जीवन में उपयोगी जानकारी, वित्तीय साक्षरता, सामाजिक जागरूकता और नागरिक कर्तव्यों से भी परिचित कराया जाता है। इससे वे न केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में वयस्क साक्षरता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करना एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक कारणों से कभी विद्यालय नहीं जा सके। कई महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने ऐसे लोगों तक पहुंचकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस साक्षरता कार्यक्रम में विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी इस अभियान की बड़ी उपलब्धि रही है। जब कोई महिला साक्षर बनती है तो उसका प्रभाव केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। साक्षर महिला अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक होती है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को बेहतर ढंग से समझती है और आर्थिक गतिविधियों में भी अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती है। इस दृष्टि से यह अभियान महिला सशक्तीकरण का भी एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। साक्षरता का सीधा संबंध आर्थिक विकास से भी है। आज के समय में बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान, सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए बुनियादी शिक्षा आवश्यक हो गई है। साक्षर व्यक्ति सरकारी दस्तावेजों को समझ सकता है, आवेदन पत्र भर सकता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है। इससे उसकी आर्थिक भागीदारी बढ़ती है और आत्मनिर्भरता को बल मिलता है। प्रदेश में अब तक आयोजित सात साक्षरता मूल्यांकन परीक्षाएं इस कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण हैं। वर्ष 2022–23 में जहां लगभग 1.46 लाख प्रतिभागियों ने परीक्षा में भाग लिया, वहीं वर्ष 2025–26 तक यह संख्या बढ़कर 4.01 लाख से अधिक हो गई। समाज के इस अभियान के प्रति लोगों का विश्वास और सहभागिता लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों का सफल होना यह भी बताता है कि साक्षरता कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वास्तविक परिणाम देने वाला अभियान बन चुका है। योगी सरकार वर्ष 2026–27 में इस अभियान को और अधिक व्यापक बनाने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप सभी जनपदों को 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें साक्षर बनाने का लक्ष्य सौंपा गया है। इसके लिए वालंटियर्स और मास्टर ट्रेनर्स का नेटवर्क और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही अभियान की नियमित मॉनिटरिंग और मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके। यह अभियान सामाजिक समरसता और समावेशी विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा का लाभ समाज के उन वर्गों तक पहुंच रहा है जो लंबे समय तक इससे वंचित रहे। इससे सामाजिक असमानताओं को कम करने और समान अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। शिक्षा के माध्यम से नागरिक अधिक जागरूक बन रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है। आज जब उत्तर प्रदेश शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल सशक्तीकरण और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, तब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इस परिवर्तन की मजबूत नींव के रूप में सामने आया है। यह अभियान केवल निरक्षरता दूर करने का प्रयास नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में कदम है जहां प्रत्येक नागरिक शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर हो। आने वाले वर्षों में यह अभियान और अधिक लोगों के जीवन में शिक्षा का प्रकाश पहुंचाएगा तथा आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त उत्तर प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। शिक्षा के इस महाअभियान ने यह साबित कर दिया है कि अक्षर ज्ञान केवल शब्दों को पढ़ने की क्षमता नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाली शक्ति है।

धर्मवीर खरे

गाज़ियाबाद की फरजाना ने विद्युत सखी बनकर ग्रामीण महिला स्वावलंबन की दी मिसाल

इस स्वावलंबी व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक साहूकारों और बिचौलियों के सामाजिक व आर्थिक शोषण से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं की कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 'रिवॉल्विंग फंड' और 'कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड' जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। इस सुदृढ़ संबल का उपयोग करके महिलाएं सिलाई-कढ़ाई, डेयरी फार्मिंग और उन्नत हस्तशिल्प जैसे स्वरोजगार अपना रही हैं। वित्तीय समावेशन को और विस्तार देते हुए राज्य में 'बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी' (बीसी सखी) और 'विद्युत सखी' जैसी अभिनव पहल लागू की गई हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वाइप मशीनों तथा मोबाइल ऐप्स से जोड़ा गया है। ये सखियां अब सुदूर गांवों में घर-घर जाकर वित्तीय सेवाएं दे रही हैं और बिजली बिल जमा कर रही हैं, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को शहरों या सब-स्टेशनों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। ऐसी ही सरकारी योजनाओं के सफल लाभार्थियों में एक प्रेरणादायी उदाहरण गाजियाबाद जिले के मुरादनगर ब्लॉक स्थित ग्राम बसंतपुर सैथली की रहने वाली फरजाना का भी है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आर्थिक और सामाजिक बदलाव की एक प्रभावशाली क्रांति ला रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को केवल वित्तीय अनुदान देने तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें स्थायी आजीविका के विविध अवसरों से जोड़कर विकास की मुख्यधारा में स्थापित करना है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के केंद्र बिंदु में ग्रामीण महिलाएं हैं, जिन्हें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के रूप में संगठित कर एक शक्तिशाली सामाजिक और वित्तीय नेटवर्क में बदला जा रहा है। ये समूह महिलाओं को एक ऐसा प्रगतिशील और सुरक्षित मंच प्रदान करते हैं, जहाँ वे अपनी छोटी–छोटी बचत को एकत्रित कर सकती हैं। इन समूहों के माध्यम से आपस में ही आसान शर्तों पर आंतरिक ऋण की व्यवस्था होती है, जिससे सदस्य महिलाएं अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को बिना किसी बाहरी निर्भरता के पूरा कर पाती हैं। इस स्वावलंबी व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक साहूकारों और बिचौलियों के सामाजिक व आर्थिक शोषण से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं की कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 'रिवॉल्विंग फंड' और 'कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड' जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। इस सुदृढ़ संबल का उपयोग करके महिलाएं सिलाई–कढ़ाई, डेयरी फार्मिंग और उन्नत हस्तशिल्प जैसे स्वरोजगार अपना रही हैं। वित्तीय समावेशन को और विस्तार देते हुए राज्य में 'बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी' (बीसी सखी) और 'विद्युत सखी' जैसी अभिनव पहल लागू की गई हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वाइप मशीनों तथा मोबाइल ऐप्स से जोड़ा गया है। ये सखियां अब सुदूर गांवों में घर–घर जाकर वित्तीय सेवाएं दे रही हैं और बिजली बिल जमा कर रही हैं, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को शहरों या सब–स्टेशनों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। ऐसी ही सरकारी योजनाओं के सफल लाभार्थियों में एक प्रेरणादायी उदाहरण गाजियाबाद जिले के मुरादनगर ब्लॉक स्थित ग्राम बसंतपुर सैथली की रहने वाली फरजाना का भी है। मेरठ जिले के माछरा गाँव के एक अत्यंत निर्धन परिवार में जन्मीं फरजाना का शुरुआती जीवन गहन संघर्षों में बीता। कम उम्र में माता के निधन के बाद उनके पिता ने रिक्शा चलाकर छह बच्चों का भरण–पोषण किया। विवाह के पश्चात बसंतपुर सैथली आने पर फरजाना के जीवन में वास्तविक और युगांतरकारी मोड़ वर्ष 2017 में आया, जब वे इस मिशन के तहत गठित 'आशीर्वाद सखी' स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं। शुरुआती बैठकों और तकनीकी बारीकियों को समझने में कठिनाइयों के बावजूद फरजाना ने हार नहीं मानी। योजना से मिले संबल और आत्मविश्वास के कारण उन्होंने अपनी अधूरी शिक्षा पुन: प्रारंभ की और वर्ष 2023 में स्नातक (बीए) की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण स्वच्छता अभियान में भी अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। वर्तमान में फरजाना 'महिला शक्ति' क्लस्टर और 'सफलता महिला प्रेरणा ग्राम संगठन' के अंतर्गत 'विद्युत सखी' के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी हैं। वे घर–घर जाकर बिजली बिलों का संकलन करती हैं और उपभोक्ताओं को सरकारी योजनाओं की प्रामाणिक जानकारी देती हैं। इस सेवा के माध्यम से उन्होंने अब तक चार करोड़ रुपये से अधिक के बिजली बिलों का कलेक्शन किया है, जिससे उन्हें ढाई लाख रुपये से अधिक का लाभांश प्राप्त हुआ है। यह 'विद्युत सखी' मॉडल यूपी पावर कॉर्पोरेशन के राजस्व प्रबंधन को सुदृढ़ करने के साथ–साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाकर पुरुषों पर उनकी पारंपरिक निर्भरता को समाप्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अब उन्नत कृषि पद्धतियों और ई–कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराकर गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को भी रोक रहा है। प्रदेश सरकार की नीतियों के समन्वय से यह मिशन अब एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जहाँ फरजाना जैसी साधारण महिलाएं अपने कड़े परिश्रम से आर्थिक स्वतंत्रता की नई पटकथा लिख रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अब परंपरागत कृषि के ढर्रे से आगे बढ़कर ग्रामीण परिवारों को वैज्ञानिक पशुपालन और जैविक खेती के आधुनिक तौर.तरीकों से भी जोड़ रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्कृष्ट उत्पादों को बेहतर और बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय प्रदर्शनियों, मेलों से लेकर बड़े ई.कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इस सुनियोजित विपणन व्यवस्था से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह तेज हुआ है। सामुदायिक आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तीकरण का यह समग्र मॉडल अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलेए ब्लॉक और सुदूर ग्राम पंक्ति तक अपनी पैठ बना चुका है। जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग और प्रदेश सरकार की लोक.कल्याणकारी नीतियों के समन्वय से यह मिशन अब एक सामान्य सरकारी योजना के दायरे से बाहर निकलकर एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की साधारण महिलाएं आज इस मिशन से जुड़कर अपने अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता और कड़े परिश्रम के बल पर विकास की एक नई पटकथा लिख रही हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सामाजिक समरसता और आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करेगी।

जनपद-गाज़ियाबाद

क्षणिक वैराग्य का भ्रम और आदमी का मसानिया सच

मनुष्य जितना आधुनिक होता जा रहा है, उतना ही भीतर से विरोधाभासों का शिकार भी होता जा रहा है। ज्ञान, नैतिकता, संस्कार और वैराग्य पर लंबे लंबे भाषण देना आज आसान हो गया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में उतारना पहले से कहीं अधिक कठिन प्रतीत होता है। यही कारण है कि आज समाज में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो दूसरों को जीवन जीने की सीख तो बड़े आत्मविश्वास से देते हैं, लेकिन स्वयं उसी कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते। हर व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी और विवेकशील मानता है, लेकिन अपने से अधिक बुद्धिमान किसी दूसरे को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाता। विडंबना यह है कि व्यक्ति स्वयं चाहे झूठ बोले या झूठ के सहारे जीवन बिताए, लेकिन दूसरों से हमेशा सत्य की अपेक्षा रखता है। शायद इसी सत्य को हमारे पूर्वजों ने वर्षों पहले एक पंक्ति में समेट दिया था 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे।' आज का मनुष्य स्वयं को सबसे अधिक समझदार और अनुभवी मानता है। उसे अपने दोष दिखाई नहीं देते, लेकिन दूसरों की छोटी सी भूल भी बड़ी नजर आती है। स्वयं झूठ और स्वार्थ से समझौता कर लेने वाला व्यक्ति भी दूसरों से ईमानदारी और आदर्शवाद की अपेक्षा करता है। यही हमारे समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। वर्तमान समाज में ज्ञान का प्रदर्शन बढ़ा है, लेकिन आत्ममंथन कम हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक बैठकों तक हर कोई जीवन दर्शन, अध्यात्म और मानवीय मूल्यों पर उपदेश देता दिखाई देता है। आज के व्यक्ति की एक और विशेषता यह है कि उसे अपने घर परिवार से अधिक संसार भर का ज्ञान रहता है और वह अपने इस तथाकथित ज्ञान का प्रदर्शन भी पूरे आत्मविश्वास के साथ करता रहता है। वह वैराग्य, अध्यात्म और जीवन दर्शन पर ऐसी ऐसी बातें करता है कि क्षणभर के लिए लगता है मानो कोई महापुरुष हमारे सामने बैठा हो। किंतु परिस्थितियां बदलते ही वही व्यक्ति अपने सारे आदर्श भूल जाता है। उसका वैराग्य स्थायी नहीं, बल्कि परिस्थितिजन्य होता है। यदि सच कहा जाए तो आज अधिकांश व्यक्ति 'मसानिया वैराग्य' का शिकार है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर एकत्रित लोगों की बातें ध्यान से सुनिए। उस समय वैराग्य और जीवन दर्शन की गंगा बहती हुई प्रतीत होती है। लोग कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सभी से प्रेमपूर्वक मिल–जुलकर रहना चाहिए। धन के पीछे अंधी दौड़ नहीं लगानी चाहिए और पैसे के कारण रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पैसा जीवन में सब कुछ नहीं होता, प्रेम, अपनापन और व्यवहार ही जीवन की वास्तविक पूंजी हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि अब सभी लोग अपने जीवन की दिशा बदल देंगे। लेकिन यही वैराग्य अधिक देर तक टिक नहीं पाता। मृतक की चिता की अग्नि शांत होने से पहले ही लोगों की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। कपाल क्रिया पूरी होने से पहले ही मोबाइल फोन बजने लगते हैं, व्यापार की बातें शुरू हो जाती हैं, राजनीति पर चर्चा होने लगती है और जीवन फिर उसी गति से स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और मोह माया की ओर लौट पड़ता है। यही वह क्षण है, जहां तथाकथित वैराग्य का वास्तविक चेहरा सामने आ जाता है। आज रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि संवेदनाएं भी औपचारिकता बनती जा रही हैं। जीवित व्यक्ति के लिए समय निकालना कठिन लगता है, लेकिन उसके निधन पर सामाजिक उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक समझा जाता है। कई लोग अंतिम यात्रा में भी इसलिए शामिल होते हैं कि समाज उन्हें संवेदनशील समझे। दुख की अभिव्यक्ति भी अब कई बार हृदय से अधिक सामाजिक दायित्व का निर्वहन बनकर रह गई है। यदि मृत आत्मा सब कुछ देख रही हो, तो शायद वह भी यही पूछे जिन लोगों का प्रेम आज उमड़ रहा है, वे मेरे जीवित रहते कहां थे? वास्तव में समस्या मृत्यु नहीं, बल्कि हमारी स्मृति की अल्पायु है। श्मशान हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाता है, लेकिन हम उस सत्य को घर लौटते–लौटते भूल जाते हैं। इसलिए हमारा वैराग्य शाश्वत नहीं, केवल 'मसानिया वैराग्य' बनकर रह जाता है ऐसा वैराग्य जो चिता की लपटों के साथ जन्म लेता है और राख ठंडी होते ही समाप्त हो जाता है। जीवन का वास्तविक वैराग्य श्मशान में नहीं, बल्कि व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि हम सचमुच यह मानते हैं कि जीवन अनिश्चित है, तो हमें अपने रिश्तों में प्रेम बढ़ाना होगा, अहंकार कम करना होगा, क्षमा करना सीखना होगा और धन को साधन मानना होगा, साध्य नहीं। मृत्यु का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अंतत: मनुष्य अपने साथ न धन ले जाता है, न पद और न प्रतिष्ठा; वह पीछे छोड़ जाता है तो केवल अपने व्यवहार की स्मृतियां। यदि श्मशान से लौटते समय हम अपने भीतर थोड़ा–सा भी स्थायी परिवर्तन लेकर लौटें, तभी उस वैराग्य का अर्थ है। अन्यथा चिता की अग्नि की तरह हमारा वैराग्य भी कुछ देर धधक कर राख हो जाएगा और हम फिर उसी मोह, माया और दिखावे की दुनिया में खो जाएंगे। यही आधुनिक मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और समाज की सबसे गंभीर विडंबना है।

अरविंद रावल

स्वामी– स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

बिसवां के किसान को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में प्रथम स्थान, जिले के लिए गौरव का क्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर) जनपद सीतापुर की तहसील बिसवां के प्रगतिशील आम उत्पादक किसान एवं पेशे से प्रवक्ता अनस ज़मीर ने उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2026 में लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त कर जनपद सीतापुर का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। महोत्सव में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए किसानों एवं बागवानों ने प्रतिभाग किया, जहाँ 800 से अधिक किस्मों के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि राज्य मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह ने अनस ज़मीर को प्रथम पुरस्कार, प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया।

उल्लेखनीय है कि अनस ज़मीर ने वर्ष 2025 में पहली बार प्रतिभाग करते हुए ही प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तथा वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान हासिल कर इस उपलब्धि को और भी ऐतिहासिक बना दिया। यह सफलता न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे जनपद सीतापुर एवं बिसवां क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। किसान अनस ज़मीर पिछले चार वर्षों से अपने पैतृक बागों का संरक्षण कर रहे हैं। वे आम की दुर्लभ एवं पारंपरिक किस्मों को संरक्षित करने के साथ-साथ नई उन्नत किस्मों का विकास भी कर रहे हैं। 'हाजी अमीर ऑर्चर्ड' ब्रांड के माध्यम से वे आम की विभिन्न उत्कृष्ट किस्मों को देशभर के लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल आम का उत्पादन करना नहीं, बल्कि लगभग सौ वर्षों पुरानी पारिवारिक विरासत, गुणवत्ता और पारंपरिक स्वाद को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुँचाना है। अपनी इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत, परिवार के सहयोग तथा उद्यान विभाग और कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने विशेष रूप से उद्यान अधिकारी सुश्री राजश्री, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. दया एस.श्रीवास्तव, अपने परिवार तथा सभी शुभचिंतकों के प्रति आभार व्यक्त किया। लगातार दो वर्षों तक प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर अनस ज़मीर ने न केवल अपने परिवार की विरासत को नई पहचान दिलाई है, बल्कि जनपद सीतापुर का नाम भी पूरे उत्तर प्रदेश में गौरवान्वित किया है।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 81 दिवसीय गौरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा पहुंची बिसवां

बिसवां/सीतापुर। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 81 दिवसीय गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा मंगलवार को बिसवां पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र एवं ताल मखाने के फूलों से तैयार विशेष मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। पत्थर शिवाला धाम के सामने एवं बाबा मनसाराम चुंगी के निकट आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना है और यह अभियान मांग पूरी होने तक निरंतर चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं है। जो भी दल गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा, उन्हें उसी का समर्थन मिलेगा उन्होंने आरोप लगाया कि अनेक संतों की मांग के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया है। सभा के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उपस्थित श्रद्धालुओं को गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास 5-कालिदास मार्ग, लखनऊ पर हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें निजी क्षेत्र में तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रसार और गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगी। लोक भवन के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत मूल्यांकन के बाद तीन संस्थाओं को आशय पत्र (एलओपी) जारी करने और संचालन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है। उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक उच्च शिक्षा पहुंचे, यह मुख्यमंत्री योगी जी का लक्ष्य है और सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। प्रायोजक संस्था 'स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती चौरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली' द्वारा कानपुर नगर की तहसील बिल्हौर के ग्राम गदनपुर आहार में 51.739 एकड़ भूमि पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की

जाएगी। यह कृषि आधारित विश्वविद्यालय होगा, जो प्रदेश में कृषि शिक्षा व अनुसंधान को नई दिशा देगा। इसके लिए उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2026 प्रख्यापित किया जाएगा। प्रायोजक संस्था 'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसाइटी, गाजियाबाद' द्वारा संचालित यह विश्वविद्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र के ग्राम डासना में 26.2656 एकड़ भूमि पर बनेगा। संस्था पहले से मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित कर रही है। अब गाजियाबाद शहर में यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के नए अवसर देगा। इसके लिए उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 प्रख्यापित होगा। प्रायोजक संस्था 'एंग्लो संस्कृत कॉलेज, फतेहपुर' द्वारा फतेहपुर तहसील के कस्बा फतेहपुर दक्षिणी में 20.45 एकड़ भूमि पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। शहरी क्षेत्र के मानक के अनुरूप 20 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध है। इसके लिए उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश, 2026 प्रख्यापित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में उच्च शिक्षा ने गुणवत्ता के साथ-साथ प्रसार में भी बड़ी छलांग लगाई है। अंग्रेजों के काल से 2017 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 14 सरकारी विश्वविद्यालय थे। 2017 से अब तक 8 नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। इसी तरह 2017 तक मात्र 27 निजी विश्वविद्यालय थे, जो अब बढ़कर 56 हो जाएंगे। तीनों प्रस्तावित विश्वविद्यालय सभी मानकों को पूरा कर रहे हैं। इनके खुलने से युवाओं को प्रदेश में ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, शोध और रोजगारपरक पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को लखनऊ स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी डॉ. मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उनके विचार और आदर्श आज भी समाज एवं युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के भारत से पूर्ण एकीकरण के मुद्दे पर डॉ. मुखर्जी के योगदान को देश सदैव याद रखेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।

मांगों को लेकर ऑटो-लोडर चालकों का परिवहन आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 6 जुलाई उत्तर प्रदेश ऑटो-लोड संयुक्त कल्याण समिति (पंजीकृत) के बैनर तले सोमवार को हल्के भार वाहन (छोटे हाथी/पिकअप) चालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लखनऊ स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार एवं परिवहन विभाग के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से पिंडदान कर विरोध जताया और बाद में परिवहन आयुक्त को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल ने कहा कि डीसीएम एवं अन्य बड़े वाहनों की तरह छोटे हाथी (पिकअप) वाहनों को भी ओवरलोड सीमा में व्यावहारिक छूट दी जानी चाहिए। मामूली ओवरलोड पर भारी-भरकम चालान किए जाने से गरीब वाहन चालकों का आर्थिक शोषण हो रहा है और उनके सामने रोज़गार का संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश

उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार रतन ने कहा कि प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में एंट्री शुल्क एवं अन्य शुल्कों में एकरूपता लागू की जाए, ताकि छोटे वाहन चालकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। प्रदेश सचिव अंकुर गुप्ता ने मांग की कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सरचार्ज माफी एवं टैक्स छूट का लाभ सभी पात्र वाहन स्वामियों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए तथा परिवहन विभाग के पोर्टल पर इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनुज यादव ने कहा कि टोल प्लाजा शुल्क, ओवरलोड जुर्माना एवं अन्य नियमों में छोटे व्यावसायिक वाहन चालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक संशोधन किए जाएं, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका सुरक्षित रह सके। समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेशभर के हल्के भार वाहन चालक लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजू (राजीव) जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार रतन, प्रदेश सचिव अंकुर गुप्ता, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनुज यादव, शमशाद अली गुड्डू सहित बड़ी संख्या में वाहन चालक एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

आगरा-लखनऊ और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए 75 करोड़ मंजूर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ?75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि परियोजना के लिए बजट में निर्धारित ?250 करोड़ के प्रावधान के तहत जारी की गई है। प्रस्तावित प्रवेश-नियंत्रित (एक्सेस कंट्रोल्ड) ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद के रास्ते आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। परियोजना का उद्देश्य प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और मजबूत बनाना तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच तेज और निर्बाध संपर्क उपलब्ध कराना है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, परियोजना पूरी होने के बाद हरदोई, फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। इससे यात्रा समय में कमी आने के साथ औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह परियोजना आधुनिक सड़क अवसंरचना के विकास, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।

संक्षिप्त खबरें

कृषि विपणन योजना के 12 निर्माणाधीन कार्यों के लिए 3.66 करोड़ की धनराशि जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि विपणन योजना के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में संचालित 12 निर्माणाधीन कार्यों को पूरा कराने के लिए ?3 करोड़ 66 लाख 70 हजार की अवशेष धनराशि जारी कर दी है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार, जारी की गई धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों को पूरा करने में किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराए जाएँ। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) तथा कार्यस्थल के फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का सत्यापन किया जा सके।

मुख्यमंत्री ग्राम योजना: 17 सड़कों के निर्माण कार्यों के लिए 9.93 करोड़ जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत विभिन्न जनपदों में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन 17 मार्गों के कार्यों के लिए ?9 करोड़ 93 लाख 17 हजार की अवशेष धनराशि जारी कर दी है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। जारी शासनादेश के अनुसार, आवंटित धनराशि का उपयोग केवल संबंधित निर्माण कार्यों पर निर्धारित मानकों एवं तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप ही किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस राशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए। कार्य पूर्ण होने के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) तथा कार्यस्थलों के फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा, ताकि कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।

आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च के बी.फार्म 2022-26 बैच का शानदार परिणाम, रश्मि सिंह रहीं अव्वल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च, सीतापुर के बी.फार्म 2022-26 बैच के विद्यार्थियों ने अंतिम वर्ष के परिणाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए संस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। विद्यार्थियों के उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन ने यह सिद्ध कर दिया कि निरंतर मेहनत, अनुशासन एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन से सफलता के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। संस्थान फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं आधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए जाना जाता है। जारी समग्र सीजीपीए परिणाम में छात्रा रश्मि सिंह ने 8.52 सीजीपीए प्राप्त कर पूरे बैच में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं मुदस्सिरा राहत ने 8.35 सीजीपीए के साथ द्वितीय स्थान तथा नीरज कुमार ने 8.33 सीजीपीए प्राप्त कर तृतीय स्थान अर्जित किया। तीनों विद्यार्थियों की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे संस्थान को गौरवान्वित किया है। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की चार वर्षों की सतत मेहनत, नियमित अध्ययन और शिक्षकों के मार्गदर्शन

का परिणाम है। संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखते हुए उन्हें व्यावसायिक दक्षता, अनुसंधान की सोच तथा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए तैयार करना है। इस अवसर पर कॉलेज परिवार ने सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। प्रबंध निदेशक जी ने विश्वास व्यक्त किया कि बी.फार्म 2022-26 बैच के विद्यार्थी भविष्य में फार्मास्यूटिकल उद्योग, अस्पताल, अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन करेंगे।

अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम का बड़ा प्रहार, जोन-3 और जोन-4 में चला सघन अभियान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। शहर में लगातार बढ़ते अवैध अतिक्रमण और उससे उत्पन्न यातायात अवरोधों को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ नगर निगम ने सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में सघन और बहुस्तरीय अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के आदेश पर की गई कार्रवाई का उद्देश्य प्रमुख सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कर नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना रहा। अभियान के दौरान जोन-3 और जोन-4 में अस्थायी कब्जे हटाए गए, सामान जब्त किया गया तथा गंदगी और प्रतिबंधित प्लास्टिक के मामलों में जुर्माना वसूला गया। जोन-4 में सहायक नगर आयुक्त एवं जोनल अधिकारी श्रीमती शिल्पा कुमारी जी के नेतृत्व में गोमती नगर विस्तार सेक्टर-5 सब्जी मंडी सहित आसपास के क्षेत्रों में

अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान झुग्गी-झोपड़ियों, ठेले-ठेलियों और सड़क किनारे किए गए अस्थायी कब्जों को हटाया गया। इसके अतिरिक्त पीली कॉलोनी से एमआई कोर्ट अपार्टमेंट तक भी अभियान चलाकर सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जोन-4 प्रवर्तन दल-296 की मौजूदगी में कर अधीक्षक श्री राज नारायण कमल जी और राजस्व निरीक्षक आकर्ष श्रीवास्तव की देखरेख में कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए कब्जों को हटाकर अवरुद्ध यातायात को सुचारु कराया गया। मौके से दो मुर्गे की जालियां और दो लकड़ी की मेज जब्त की गईं। अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को दोबारा कब्जा न करने की चेतावनी भी दी। जोन-4 में अतिक्रमण हटाने के साथ ही गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। अतिक्रमण एवं गंदगी से जुड़े मामलों में चालान कर ?7,600 का जुर्माना वसूला गया, जबकि प्रतिबंधित प्लास्टिक के मामलों में ?10,000 का जुर्माना लगाया गया। अभियान में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक रश्मि शुक्ला जी, बाल गोविंद जी और राकेश कुमार वर्मा जी उपस्थित रहे। जोन-3 में जोनल अधिकारी मनोज यादव जी के निर्देश पर प्रवर्तन दल-296 के साथ हनुमान सेतु से आठ नंबर चौराहा तक सघन अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इसके साथ ही भांडो मोहल्ला, मेवाती मोहल्ला, इरादतनगर और डालीगंज क्षेत्र में चाय की दुकानें रखकर किए गए अवैध अस्थायी कब्जों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। संवेदनशील स्थलों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय पुलिस विभाग को पत्र भी भेजा गया है। जोन-3 की कार्रवाई के दौरान लगभग 50 दुकानों के सामने किए गए अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटवाए गए। मौके से दो चटाइयां और दो ट्रैक्टर जब्त किए गए।

युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और रोजगार का बेहतर अवसर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। मुख्य सचिव एस.पी.गोयल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार एवं उद्योग के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीन योजना ISSA के प्रारूप एवं कार्यान्वयन रणनीति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों के प्रभावी अभिसरण, उद्योगों की सक्रिय सहभागिता तथा परिणाम-आधारित कार्यप्रणाली के साथ सुनिश्चित किया जाए, जिससे प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप एवं रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाएँ तथा चरणबद्ध कार्ययोजना, वित्तीय आवश्यकताओं, संस्थागत व्यवस्थाओं एवं कार्यान्वयन तंत्र का विस्तृत प्रस्ताव निर्धारित समयावधि में तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए। बैठक में राज्य, जनपद एवं क्लस्टर स्तर पर प्रभावी चार-स्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित करने, डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय (Real-time) में प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने तथा उद्योगों, एमएसएमई, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रदेश में एक सुदृढ़, उद्योगोन्मुख एवं रोजगारपरक कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र (Skilling Ecosystem) विकसित करने पर विशेष बल दिया गया।

इससे पहले बैठक में प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग डॉ0 हरि ओम द्वारा ISSA से सम्बन्धित राज्य स्तरीय प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण तथा रोजगार व उद्यमिता की प्रस्तावित एकीकृत व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया गया तथा विभिन्न विभागों एवं हितधारकों से सम्बन्धित बिन्दुओं से प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। बैठक के अंत में मुख्य सचिव के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग डॉ0 हरि ओम द्वारा समस्त विभागों एवं हितधारकों से अपेक्षा की गयी कि वे अपने-अपने विभाग एवं संस्था से सम्बन्धित प्रस्ताव व बिन्दुओं से सम्बन्धित विवरण को 01 सप्ताह की अवधि में तैयार कर निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 को उपलब्ध करा दें, जिससे कि कार्य योजना को अंतिम रुप से तैयार कराते हुये मुख्य सचिव के अनुमोदन से स्वीकृति हेतु भारत सरकार को समयबद्ध रुप से प्रेषित किया जा सके। प्रस्तुतीकरण के पश्चात बैठक में विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार तक एक समग्र एवं एकीकृत स्किलिंग इकोसिस्टम विकसित करने के विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया।

सड़क और नाली निर्माण का हुआ भव्य शिलान्यास

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र के वृंदावन योजना स्थित सेक्टर-10 C कॉलोनी में वर्षों से प्रतीक्षित सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि-विधान के साथ भव्य शिलान्यास किया गया। जागरण वाले पार्क के चारों ओर प्रस्तावित सड़क एवं नाली निर्माण का शुभारंभ सरोजिनी नगर के लोकप्रिय विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के प्रतिनिधि डॉ. अखिलेश सिंह ने किया। शिलान्यास समारोह में बड़ी संख्या में कॉलोनी वासियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। पूजन-अर्चन का विधिवत आयोजन पंडित रामजी दुबे द्वारा संपन्न कराया गया। शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में डॉ. अखिलेश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार और विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा और पूरी गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर

आवागमन और जलनिकासी की सुविधा मिल सके। इस अवसर पर कॉलोनीवासियों ने डॉ. अखिलेश सिंह का पुष्पमालाओं, स्मृति-चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट कर भव्य स्वागत किया। समारोह के दौरान 'भारत माता की जय' और 'जय श्रीराम' के गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति और उत्साह से गूंज उठा। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी रत्नाकर त्रिपाठी, इंस्पेक्टर फूल बदन सिंह, इंजीनियर रामप्रसाद, इंजीनियर लाल बहादुर पांडेय, इंजीनियर हिमांशु सिंह सहित अनेक प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा दीपक शुक्ला, महेंद्र कुमार मिश्रा, नवीन कुमार पाठक, रमेश चौधरी, विजय यादव, स्वामीनाथ सरोज, संजय चौबे, डॉ. चंद किशोर पांडे, रंजय सिंह, अंकित गौड़, एल.बी. सिंह पटेल, एस.के. सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की।

श्रीलंका की जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प: 25 की मौत, 100 घायल

इस हिंसा के बाद श्रीलंकाई सेना को मदद के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को काबू करने के लिए सेना से समर्थन मांगा। यह झड़प रविवार को शुरू हुई थी, जब दोषी कैदियों और हिरासत में रखे गए कैदियों के बीच संघर्ष हुआ। यह घटना श्रीलंका के तटीय शहर नेगोम्बो की एक अधिक भीड़भाड़ वाली जेल में हुई। रॉयटर्स ने यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है।स्थानीय टेलीविजन चैनल हिरू के अनुसार, मृतकों में कैदी और जेल अधिकारी दोनों शामिल हैं। यह जेल कोलंबो से करीब 35 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। झड़प किस कारण शुरू हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

लेकिन बताया जा रहा है कि सोमवार को हिंसक झड़प के दौरान कुछ कैदियों ने जेल के हथियार छीन लिए, जिसके बाद हिंसा और बढ़ गई और स्थिति घातक हो गई।रॉयटर्स ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि जेल के कुछ हिस्सों में अभी भी तलाशी और सफाई का काम चल रहा है और मृतकों व घायलों की सही संख्या का पता लगाया जा रहा है।

कोलंबो(एजेंसी)। श्रीलंका में सोमवार को कैदियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 25 लोगों की मौत हो गई। करीब 100 लोग घायल हो गए। मृतकों में जेल अधिकारियों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इस हिंसा के बाद श्रीलंकाई सेना को मदद के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को काबू करने के लिए सेना से समर्थन मांगा। यह झड़प रविवार को शुरू हुई थी, जब दोषी कैदियों और हिरासत में रखे गए कैदियों के बीच संघर्ष हुआ। यह घटना श्रीलंका के तटीय शहर नेगोम्बो की एक अधिक भीड़भाड़ वाली जेल में हुई। रॉयटर्स ने यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है।स्थानीय टेलीविजन चैनल हिरू के अनुसार, मृतकों में कैदी और जेल अधिकारी दोनों शामिल हैं। यह जेल कोलंबो से करीब 35 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। झड़प किस कारण शुरू हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

लेकिन बताया जा रहा है कि सोमवार को हिंसक झड़प के दौरान कुछ कैदियों ने जेल के हथियार छीन लिए, जिसके बाद हिंसा और बढ़ गई और स्थिति घातक हो गई।रॉयटर्स ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि जेल के कुछ हिस्सों में अभी भी तलाशी और सफाई का काम चल रहा है और मृतकों व घायलों की सही संख्या का पता लगाया जा रहा है। श्रीलंकाई सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर वारुणा गामागे ने बताया कि सेना को पुलिस की मदद के लिए बुलाया गया है। लेकिन फिलहाल वे तैयार स्थिति में हैं। डेराना समेत कई टेलीविजन चैनलों के वीडियो फुटेज में दिखाया गया कि एक पुलिस बस घायलों को ले जा रही है। कुछ घायल कैदी बस के फर्श पर पड़े हुए थे। जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी: अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली(एजेंसी)। भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर भारतीय रेलवे ने विशेष तैयारियां की हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रथ यात्रा के दौरान 300 से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा केरल में ओणम त्योहार के लिए भी 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ मिलकर ओडिशा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ की आगामी रथ यात्रा के लिए भारतीय रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया। अश्विनी वैष्णव ने भीड़ प्रबंधन, यात्रियों की आवाजाही और ऑपरेशनल तैयारियों सहित रेलवे की व्यवस्थाओं का समग्र मूल्यांकन किया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें त्योहार के सुचारू संचालन के लिए की गई एकीकृत व्यवस्थाओं और विस्तृत ऑपरेशनल योजना के बारे में जानकारी दी। सीएम माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ पवित्र शहर पुरी में नई 'पुरी-कोरापुट-पुरी' ट्रेन का उद्घाटन किया, जो श्रीक्षेत्र को शबर श्रीक्षेत्र से

सीधे जोड़ती है। तटीय, पश्चिमी और दक्षिणी ओडिशा को जोड़ने वाली यह नई ट्रेन जगन्नाथ भक्तों के लिए एक अनूठा उपहार है। इस शुभ अवसर पर भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। यात्रा में लाखों भक्तों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए, भारतीय रेलवे ने सैकड़ों विशेष ट्रेनें चलाने, बड़े होल्डिंग एरिया, खान-पान और अतिरिक्त टिकट काउंटर जैसी अपनी सेवाओं को मजबूत किया है। उन्होंने आगे लिखा कि पीएम मोदी के के नेतृत्व में राज्य में सालाना रेलवे बजट में काफी बढ़ोतरी हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है। 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत, पुरी रेलवे स्टेशन को भी उसकी सांस्कृतिक भव्यता को ध्यान में रखते हुए विश्व-स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रभु के आशीर्वाद से, यह सर्वांगीण विकास और राज्य के सभी जिलों तक रेल कनेक्टिविटी हमें एक समृद्ध ओडिशा और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में और आगे ले जाएगी। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में निर्माणाधीन पुरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर में चल रहे विभिन्न विकास एवं आधुनिकीकरण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने, स्टेशन की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने तथा महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पावन रथयात्रा सहित वर्षभर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया गया।

पात्रा ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा ज्यादा सुविधाजनक और आसान हो सके।

रोजाना शराब की एक ड्रिंक भी बढ़ा सकती है हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा

रोजाना सिर्फ एक शराब की ड्रिंक भी आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। इससे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ सकता है जो आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। 'हाइपरटेंशन' (अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक जर्नल) में प्रकाशित इस स्टडी में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के करीब 19,548 से ज्यादा लोगों के डेटा को शामिल किया गया। इन लोगों की सेहत को कई सालों तक ट्रैक किया गया ताकि यह समझा जा सके कि शराब पीने और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बीच क्या संबंध है। शोधकर्ताओं ने पाया कि शराब की मात्रा और ब्लड प्रेशर के बीच एक सीधा संबंध है। जैसे-जैसे रोजाना शराब का सेवन बढ़ता है, वैसे-वैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर (दिल द्वारा शरीर में रक्त पंप करने का दबाव) में भी बढ़ोतरी होती है। अध्ययन के अनुसार, कम मात्रा में शराब पीने वाले लोगों में भी ब्लड प्रेशर में हल्की लेकिन लगातार वृद्धि दर्ज की गई। इसका मतलब यह है कि भले ही शुरुआती स्तर पर यह बदलाव बहुत बड़ा न लगे, लेकिन लंबे समय में यह हृदय और रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ा सकता है। यह

स्थिति आगे चलकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके अलावा, अध्ययन में यह भी देखा गया कि पुरुषों में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर (जो दिल की धड़कनों के बीच रक्त वाहिकाओं में दबाव को मापता है) में वृद्धि हुई, जबकि महिलाओं में यह प्रभाव स्पष्ट रूप से नहीं देखा गया। यह निष्कर्ष मिरर की रिपोर्ट में भी सामने आया। अध्ययन के प्रमुख लेखक प्रोफेसर मार्को विंसेटी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मोडेना एंड रेजियो एमिलिया से जुड़े हैं और बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एडजंक्ट प्रोफेसर भी हैं, ने कहा कि उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कम मात्रा में शराब का सेवन भी रक्तचाप में नकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा, 'हमें कम स्तर पर शराब पीने से कोई लाभकारी प्रभाव नहीं मिला, जब इसकी तुलना शराब न पीने वालों से की गई।' प्रोफेसर विंसेटी ने यह भी कहा कि शराब केवल ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि शराब का सेवन सीमित रखना चाहिए और यदि संभव हो तो इसे पूरी तरह से टालना और भी बेहतर है। ट्यूलाने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर पॉल व्हेलन, जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के अध्यक्ष भी हैं, ने इस शोध की व्याख्या करते हुए कहा कि जिन प्रतिभागियों का शुरुआती ब्लड प्रेशर पहले से ही थोड़ा बढ़ा हुआ था, उनमें शराब के प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार, आम वयस्कों में उच्च रक्तचाप आमतौर पर 140/90 एमएमएचजी या उससे अधिक माना जाता है। अध्ययन में पाया गया कि लगभग 12 ग्राम शराब प्रतिदिन लेने वालों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर औसतन 1.25 एमएमएचजी तक बढ़ गया। वहीं, जो लोग प्रतिदिन लगभग 48 ग्राम शराब का सेवन करते थे, उनमें ब्लड प्रेशर में औसतन 4.9 एमएमएचजी तक की वृद्धि देखी गई।

रहूं मैं तेरे रूबरू को लेकर संजय गुप्ता की टिप्पणी से छिड़ी बहस

'रहूं मैं तेरे रूबरू' का टीज़र रिलीज़ होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। दर्शकों ने टीज़र में दिखाए गए रोमांस, मिस्ट्री और सस्पेंस की तारीफ की है। वहीं फिल्म की नई स्टारकास्ट और अलग कहानी ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। लेकिन फिल्म की चर्चा के बीच एक ऐसा विवाद शुरू हो गया, जिसने पूरे मुद्दे को एक नई दिशा दे दी। यह फिल्म किसी बड़े सुपरस्टार, मशहूर फिल्म परिवार या बड़े बैनर की नहीं है। 'रहूं मैं तेरे रूबरू' के जरिए आर्या कुमार, नीता शेट्टी और पीहू बिस्वास जैसे नए कलाकार दर्शकों के सामने आ रहे हैं। इनके साथ पूरी टीम ने अपने सपनों और मेहनत के दम पर इस फिल्म को बनाया है। हर नए कलाकार और फिल्ममेकर की तरह इन्हें भी सिर्फ अपने काम के जरिए दर्शकों तक पहुंचने का एक मौका चाहिए। विवाद की शुरुआत तब हुई जब जाने-माने ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर फिल्म के टीज़र की तारीफ करते हुए पोस्ट शेयर की। तारण आदर्श वर्षों से छोटे-बड़े बजट और नए-पुराने सभी तरह की फिल्मों को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देते रहे हैं। उन्होंने भी इसी तरह इस फिल्म के टीज़र की सराहना की। इसके बाद निर्देशक संजय गुप्ता ने तारण आदर्श की उसी पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा– हालांकि संजय गुप्ता ने अपने पोस्ट में फिल्म का नाम नहीं लिया, लेकिन यह टिप्पणी तारण आदर्श की 'रहूं मैं तेरे रूबरू' वाले पोस्ट पर की गई थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे सीधे इस फिल्म और उसके प्रमोशन से जोड़कर देखा।

इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कई लोगों का मानना था कि इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणियां नई फिल्मों और नए कलाकारों का मनोबल गिराती हैं। लोगों

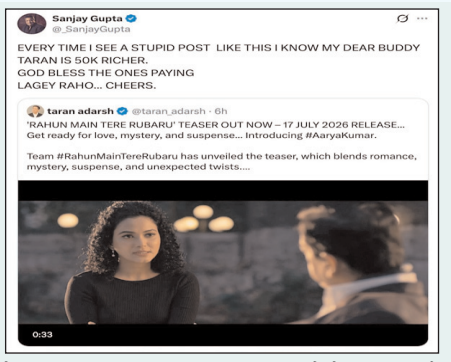

ने सवाल उठाया कि क्या बिना फिल्म देखे सिर्फ उसके प्रमोशन को लेकर इस तरह की बातें करना सही है? इस बीच वरिष्ठ पत्रकार उपाला केबीआर ने संजय गुप्ता की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि किसी वरिष्ठ ट्रेड एनालिस्ट पर इस तरह सार्वजनिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को केवल बड़े बजट की फिल्मों की नहीं, बल्कि छोटे और मिड-बजट की फिल्मों की भी जरूरत है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि नए निर्देशक, नए कलाकार और नई फिल्में भी प्रोत्साहन की हकदार हैं। हर बड़ा निर्देशक और अभिनेता कभी न कभी नया ही था। अगर शुरुआत में उन्हें मौका और समर्थन नहीं मिलता, तो वे आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते।

उपाला के इस जवाब को सोशल मीडिया पर काफी समर्थन मिला। कई लोगों ने कहा कि भारतीय सिनेमा हमेशा इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि यहां हर तरह की फिल्मों को जगह मिली। बड़े स्टार्स की फिल्मों के साथ-साथ छोटे बजट और नए फिल्मकारों की फिल्मों ने भी इंडस्ट्री को नई पहचान दी है। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है–क्या नए कलाकारों और स्वतंत्र फिल्मकारों को दर्शकों के फैसले से पहले ही हतोत्साहित किया जाना चाहिए?स्वतंत्र फिल्मकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी फिल्म को लोगों तक पहुंचाना होती है। उनके पास न बड़े स्टार होते हैं, न भारी-भरकम मार्केटिंग बजट और न ही बड़े प्रोडक्शन हाउस का सहारा। ऐसे में किसी प्रतिष्ठित ट्रेड एनालिस्ट या पत्रकार का एक सकारात्मक पोस्ट उनकी फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। बाद में सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद और प्रतिक्रियाओं के बाद संजय गुप्ता ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक यह मामला सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स और नए फिल्मकारों को मिलने वाले अवसरों और सम्मान पर बड़ी बहस बन चुका था। 'रहूं मैं तेरे रूबरू' को एस. एस. एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्रस्तुत कर रहा है। फिल्म में आर्या कुमार, नीता शेट्टी और पीहू बिस्वास मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसका निर्देशन इंदर दास ने किया है, जबकि कहानी और स्क्रीनप्ले आर्या कुमार ने लिखा है। फिल्म की निर्माता सुमन सौरभ हैं। यह फिल्म 17 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। आखिरकार, हर फिल्म का फैसला दर्शकों को उसे देखने के बाद करना चाहिए, न कि रिलीज़ से पहले। चाहे फिल्म किसी बड़े बैनर की हो या किसी नए फिल्मकार की, हर किसी को अपने काम को निष्पक्ष तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने का समान अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि भारतीय सिनेमा का इतिहास गवाह है कि हर बड़ा सितारा और हर सफल फिल्मकार कभी न कभी एक नया चेहरा था, जिसके पास सिर्फ एक सपना और खुद को साबित करने का जुनून था।

एयरटेल नेटवर्क से वंचित निबिया के आसपास के आठ गांव, हजारों लोग परेशान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि। डिजिटल इंडिया के युग में जहां देश तेज़ 4G और 5G सेवाओं की ओर बढ़ रहा है, वहीं श्रीभूमि ज़िले के रामकृष्णनगर विधानसभा निबिया के आसपास क्षेत के कालामागुरा क्षेत्र के रांगपुर ग्राम पंचायत के आठ गांव आज भी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा से वंचित हैं। दुर्गापुर, भीतरबालिया, विष्णुराम बस्ती, सर्माफा बस्ती, सातकरागेनाई, भड़बालिया, 4 नंबर भीतरबालिया और 5 नंबर बलिया गांवों के हजारों परिवार लंबे समय से खराब नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में केवल एक एयरटेल टावर मौजूद है, लेकिन उसकी क्षमता बेहद सीमित है और 4G/5G सेवाएं लगभग अनुपस्थित हैं। परिणाम

दुर्गापुर, भीतरबालिया, विष्णुराम बस्ती, सर्माफा बस्ती, सातकरागेनाई, भड़बालिया, 4 नंबर भीतरबालिया और 5 नंबर बलिया गांवों के हजारों परिवार लंबे समय से खराब नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में केवल एक एयरटेल टावर मौजूद है, लेकिन उसकी क्षमता बेहद सीमित है और 4G/5G सेवाएं लगभग अनुपस्थित हैं। परिणाम स्वरूप, मोबाइल नेटवर्क अक्सर बाधित रहता है और इंटरनेट सेवा लगभग ठप हो जाती है। इसका सीधा असर छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई, परीक्षा फॉर्म भरने, परिणाम देखने और अन्य शैक्षणिक कार्यों पर पड़ रहा है।

स्वरूप, मोबाइल नेटवर्क अक्सर बाधित रहता है और इंटरनेट सेवा लगभग ठप हो जाती है। इसका सीधा असर छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई, परीक्षा फॉर्म भरने, परिणाम देखने और अन्य शैक्षणिक कार्यों पर पड़ रहा है। इसके अलावा बैंकिंग सेवाएं, आधार से जुड़े कार्य, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और रोज़मर्रा के डिजिटल कामों के लिए ग्रामीणों को 10 से 12 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में भी बुनियादी मोबाइल नेटवर्क से वंचित रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लंबे समय से समस्या बनी रहने के कारण हजारों लोग गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, स्थानीय विधायक विजय मालाकार तथा संबंधित प्रशासन से जल्द से जल्द नए मोबाइल टावर की स्थापना या मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन की मांग की है। ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके।

रिश्वतखोरी के मामले में उत्तरी रेलवे के दो अधिकारियों समेत तीन गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित रिश्वतखोरी के एक मामले में उत्तरी रेलवे के मुख्य सामग्री प्रबंधक (सीएमएम) और एक वरिष्ठ लिपिक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सीबीआई ने शुक्रवार रात रिश्वत के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद नई दिल्ली स्थित बड़ौदा हाउस में उत्तरी रेलवे मुख्यालय पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने मुख्य सामग्री प्रबंधक (स्टोर) नरेंद्र सिंह और वरिष्ठ लिपिक लेनिन शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, 'आरोप है कि उत्तरी रेलवे मुख्यालय के ये लोक सेवक एक निजी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मिलीभगत कर भ्रष्टाचार में शामिल थे। वे कथित तौर पर अवैध रिश्वत के बदले रेलवे के ठेके दिलाने में निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचा रहे थे।' प्रवक्ता ने कहा कि सार्वजनिक खरीद से जुड़े निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर ठेके दिए गए। सीबीआई के आधिकारिक बयान के अनुसार, 'ट्रैप कार्रवाई के दौरान निजी कंपनी के प्रतिनिधि शारिक अली द्वारा उत्तरी रेलवे के मुख्य सामग्री प्रबंधक को दी गई एक लाख रुपये की रिश्वत की राशि बरामद की गई।' अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने दोनों सरकारी अधिकारियों और कथित रिश्वत देने वाले शारिक अली को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर और कानपुर स्थित विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली गई, जहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं। सीबीआई ने इस मामले में उत्तरी रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस में तैनात मुख्य सामग्री प्रबंधक नरेंद्र सिंह, उप मुख्य सामग्री प्रबंधक शुभाशीष मैती और वरिष्ठ लिपिक (स्टोर) लेनिन शर्मा को आरोपी बनाया है। प्राथमिकी में उत्तर प्रदेश के कानपुर के जाजमऊ स्थित मैश इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (मैश एंड कंपनी) के कारोबारी शारिक अली और एजाज अली के नाम भी शामिल हैं। कंपनी को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के अनुसार, शारिक अली कथित तौर पर लेनिन शर्मा और उनके सहयोगियों के माध्यम से रेलवे टेंडरों से जुड़ी 'महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी' तथा अन्य लाभ अवैध रिश्वत के बदले नियमित रूप से हासिल करता था।

जमीन तक तय नहीं हुई, लेकिन कागज़ों में छह साल से चल रहा 100 बेड का अस्पताल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना इलाके में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल को लेकर एक अजीब प्रशासनिक स्थिति सामने आई है. यह अस्पताल पिछले छह वर्षों से सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह 'संचालित' माना जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि अब तक उसकी एक भी ईंट नहीं रखी गई है. यहां तक कि अस्पताल के लिए जमीन का अंतिम चयन भी नहीं हो पाया है। छह साल पहले (साल 2020 में) मध्य प्रदेश सरकार ने खजराना में एक आधुनिक सिविल अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की थी. लेकिन अस्पताल के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश लंबी खिंचती चली गई. इसके बावजूद प्रशासनिक प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रही. स्वास्थ्य विभाग ने इस अस्तित्वहीन अस्पताल के लिए डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित 87 पदों को मंजूरी दे दी। इसके बाद वर्षों तक नियमित रूप से इन पदों पर नियुक्तियां और तबादले किए जाते रहे. अस्पताल का भवन नहीं होने के कारण इन कर्मचारियों को शहर के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, जिनमें हुकुमचंद अस्पताल, पीसी सेठी अस्पताल और अन्य सरकारी चिकित्सा संस्थान शामिल हैं, में तैनात किया जाता रहा। इस असामान्य स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने परियोजना का इतिहास बताते हुए कहा, 'शुरुआत में यहां एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित होता था।

बाद में इसे 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में उन्नत किया गया और फिर इसे 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि उपयुक्त सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं हो सका. 'जब तक अस्पताल की इमारत तैयार नहीं हो जाती, तब तक स्वीकृत कर्मचारियों को अन्य सरकारी चिकित्सा संस्थानों में तैनात किया गया है. जमीन की तलाश अभी भी जारी है.' इस बीच, इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हसानी ने निर्माण में हुई देरी की वजह बताते हुए कहा, 'शहर की सीमा के भीतर इतनी बड़ी सरकारी जमीन उपलब्ध कराना आसान नहीं है. यही कारण है कि अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि अस्पताल के लिए स्वीकृत नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारियों को संजीवनी क्लीनिकों और अन्य सरकारी अस्पतालों से संबद्ध कर दिया गया है, ताकि उनकी सेवाओं और कौशल का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

वी-केयर अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने छात्राओं को सुरक्षा का दिया मंत्र

आत्मरक्षा से साइबर सुरक्षा तक किया जागरूक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'बाल सुरक्षा जागरूकता माह' के अंतर्गत 'वी-केयर' अभियान के तहत सोमवार को ज्वालापुरी स्थित सीएम श्री स्कूल, अमलवास में छात्राओं के लिए विशेष सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को व्यक्तिगत सुरक्षा, आत्मरक्षा, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक बनाना तथा उनमें आत्मविश्वास विकसित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली पुलिस के वाद्यवृंद (ऑर्केस्ट्रा) दल द्वारा देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुति से हुई। गीतों ने छात्राओं का मन मोह लिया और पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल बना दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की विभिन्न

इकाइयों ने सुरक्षा से जुड़े विषयों पर जागरूकता सत्र आयोजित किए।महिला एवं बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ एसपीयूडब्ल्यूएसी की टीम ने छात्राओं को आत्मरक्षा का महत्व समझाया और विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा के लिए आवश्यक आत्मरक्षा के गुर सिखाए। टीम ने कई तकनीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया, जिससे छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ा।यातायात पुलिस की टीम ने छात्राओं को सड़क पर सुरक्षित चलने, यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित आवागमन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान यातायात जागरूकता वाहन के माध्यम से सड़क सुरक्षा से संबंधित शिक्षाप्रद चलचित्र भी दिखाए गए।बाहरी जिले के साइबर थाना के अधिकारियों ने छात्राओं को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, साइबर अपराध और सामाजिक माध्यमों के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इंटरनेट का सावधानी और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने की सलाह भी दी।कार्यक्रम स्थल पर दिल्ली पुलिस का जनसंपर्क वाहन भी मौजूद रहा, जिसमें बाल सुरक्षा से जुड़े जागरूकता वीडियो प्रदर्शित किए गए। इन वीडियो के माध्यम से छात्राओं को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण संदेश सरल और प्रभावी ढंग से समझाए गए।कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए सुरक्षा विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा रस्साकशी प्रतियोगिता भी कराई गई, जिससे छात्राओं में टीम भावना और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला।इस कार्यक्रम में विद्यालय की 200 से अधिक छात्राओं, शिक्षकों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिला एवं बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ की पुलिस उपायुक्त नेहा यादव (आईपीएस) ने कहा कि वी-केयर अभियान के माध्यम से दिल्ली पुलिस बच्चों विशेषकर छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ समाज और पुलिस के बीच विश्वास को भी मजबूत करते हैं।